an>

Title: Need to provide permanent land pattas to Vanya Gram (Van Tangia Gaon) set up in forest areas in Eastern Uttar Pradesh and include them in the category of Revenue villages.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) ः देश के अन्दर आजादी के पूर्व वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ब्रिटिश सरकार ने वन्य ग्राम (वन टांगिया गांव) बसाए थे। इन गांवों का उद्देश्य ग्राम समाज और सरकार की फालतू भूमि पर वन लगाने, उनकी सुरक्षा और उनके विकास का था। इसके बदले में सरकार ने उन्हें कुछ जमीन दी थी, लेकिन आज़ादी के बाद इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। पूर्वी उ.प्र. में गोरखपुर-कुशीनगर से लेकर लखीमपुर खीरी तक 56 ऐसे गांव हैं जो वन्य ग्राम (वन टांगिया गांव) हैं। जंगलों के बीच में होने के कारण कोई भी बुनियादी सुविधा इन लोगों के पास नहीं है। इन गांवों में सड़क नहीं हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार इन्हें पंचायत चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला। देश आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं लेकिन ये लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। पिछली सरकार ने इन गांवों को राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता देने के लिए कानून पास किया था और यह तय किया था कि जो परिवार 75 वर्ष से अधिक उन गांवों में रह रहे हैं उन्हें स्थायी पट्टा देकर राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की बात हुई थी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में मात्र 80 प्रतिशत लोगों को जमीन का पट्टा तो दिया गया लेकिन राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता इन्हें अब तक नहीं मिल पायी है।

हमारा आग्रह है कि भारत सरकार इसका संज्ञान ले। बुनियादी सुविधाओं से वंचित एक बड़ी आबादी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि जमीन का स्थायी पट्टा देकर उन्हें राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता दी जाए तथा इन सभी गांवों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए।